Provision for Non-plan expenditure of PSUs

3850. SHRI N. GIRI PRASAD:
SHRI GURUDAS DASGUPTA:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have not provided any money by way of non-plan expenditure during 1997-98 for Public Sector Undertakings like Scooters India Ltd. (SIL), Heavy Engineering Corporation (HEC), Hindustan Paper Corporation (HPC) and Bharat Yantra Nigam Ltd. (BYNL);

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) how the expenditure towards the salary of employees and other maintenance charges are proposed to be met during the year?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b)

Non-Plan funds budgeted for 1997-98

(Rs. in Crs.)

Sl. No.	Name of the PSU	Funds Budgeted	Remarks
1.	Scooters India Ltd. (SIL)	Nil	The Co. does not need any Non Plan support from the Government during 1997-98 due to its improved performance. The Co. earned a profit of Rs. 1.09 Crores in 1996-97.
2.	Heavy Engineering Corporation Ltd. (HEC)	Rs. 18 crs.	
3.	Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPC)	NIL	The Co. has not sought any Non Plan support from the Govt. as it expects to earn an operating profit during 1997-98.
4.	Bharat Yantra Nigam Ltd. (BYNL)	Rs. 9.70 Crs.	A sum of Rs. 5.70 Crores in respect of Triveni Structurals Ltd. (TSL) and Rs. 4 Crores in respect of Richardson & Cruddas (1972) Ltd. (R & C) (subsidiaries of BYNL) have been budgeted as Non Plan support as per the requirement of funds envisaged in the sanctioned BIFR scheme.

(c) No difficulty is envisaged in meeting the expenditure towards the salary of employees and other maintenance charges of these PSUs. This expenditure will be met from their own internal resources.

खादी के कपड़ों पर रियायत

3851. श्री राधाकिशन मालवीय: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से खादी के कपड़ों पर रियायत देना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि खादी कपड़ों पर रियायत ग्राहकों के अलावा किसी और को नहीं दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या खादी के मामले में किसी सतत् नीति के न होने से उक्त रियायत को बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपनी संस्थाओं और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों की पंजीकृत संस्थाओं के खादी के कपड़ों और पोली वस्त्रों की बिक्री पर छूट प्रदान करता है। खादी की बिक्री पर इस प्रकार की छूट केवल ग्राहकों को दी जाती है। समय-समय पर सरकार के आदेशों के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा छूट प्रदान की जाती है। 11.7.1996 को जारी किए गए पिछले आदेश में, 31.03.97 तक छूट की अनुमति दी गई थी।